शनिवार, 9 मई, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

चर्चा आज हर क्रिकेट फैन की जुबान पर, तेज गेंदबाज प्रिंस यादव

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'राजा शिवाजी' रिव्यू: भव्यता, भावनाओं और शिवराय के गौरव से भरी लेकिन बिखरी हुई कहानी

Page-05

TRE-4 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में देरी से हजारों उम्मीदवारों के भविष्य और उम्र सीमा पर संकट खड़ा हो गया है।

पटना में बवाल

शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज

- **TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी के खिलाफ पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज।**
- **46,882 शिक्षक पदों की भर्ती अटकी, सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिया।**

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च निकाला और सरकार तथा BPSC के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान हालात तब बिगड़ गए जब अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पहले से बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन छात्रों ने बैरिकेड हटाने और आगे बढ़ने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तनाव बढ़ गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया।अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से TRE-4 भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। उनका आरोप है कि लगातार हो रही देरी के कारण हजारों उम्मीदवारों की आयु सीमा समाप्त होने की कगार पर है, जिससे उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।इस मामले पर मिथलेश तिवारी ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अभ्यर्थियों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से आंदोलन की बजाय संवाद का रास्ता अपनाने की अपील करते हुए कहा, "हर समस्या का समाधान होगा और आज होगा। सरकार उनकी ही है और बातचीत से ही विवाद का हल निकलेगा।"इससे पहले अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर#Release_TRE4_Notification अभियान चलाकर अपनी मांग सरकार और BPSC तक पहुंचाने की कोशिश की थी। शिक्षा विभाग ने पहले दावा किया था कि TRE-4 भर्ती का नोटिफिकेशन 19-20 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा और 26 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन तय तारीखें गुजर जाने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक TRE-4 के तहत कुल 46,882 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। लाखों अभ्यर्थी पिछले दो वर्षों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं।

होर्मुज के पास तनाव के बीच ट्रंप का दावा- 'सीजफायर कायम'

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच घोषित सीजफायर अब भी प्रभावी है, हालांकि हाल के दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास दोनों पक्षों के बीच सैन्य तनाव और झड़पें देखने को मिली हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह संघर्षविराम टूटा, तो उसका असर बेहद बड़ा और साफ दिखाई देगा।वॉशिंगटन में लिंकन मेमोरियल के पास मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि लोगों को यह जानने के लिए किसी आधिकारिक घोषणा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सीजफायर खत्म हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा, "अगर समझौता टूटा तो ईरान से उठती रोशनी का पहाड़ दिखाई देगा।"ट्रंप ने बताया कि हालिया घटनाओं में अमेरिकी सेना ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और विरोधी ताकतों को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित हमलावरों ने अमेरिकी सेना को उकसाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी बलों ने उन्हें "पूरी ताकत से जवाब" दिया। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान के साथ भविष्य में किसी समझौते की संभावना अब भी बनी हुई है। इस बीच यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने जानकारी दी कि अमेरिकी नौसेना के तीन युद्धपोतों पर हमले किए गए थे। CENTCOM के अनुसार, यूएसएस ट्रक्सटन (DDG-103), यूएसएस राफेल पेराल्टा (DDG-115) और यूएसएस मेसन (DDG-87) होर्मुज जलडमरूमध्य से ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन पर मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नौकाओं के जरिए हमला किया गया।

मणिशंकर अय्यर बोले- 'यह सबसे खराब राजनीतिक अवसरवाद'

पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के साथ गठबंधन किए जाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस कदम को "बेहद खराब" बताते हुए कहा कि इससे निम्न स्तर की राजनीतिक अवसरवादिता की झलक मिलती है। अय्यर ने चेतावनी दी कि यदि इस फैसले से तमिलनाडु में भाजपा को "पिछले दरवाजे" से प्रवेश का मौका मिलता है, तो यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा "आत्मघाती गोल" साबित हो सकता है।अय्यर ने कहा कि वह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस के पूर्वज इस तरह की राजनीति का समर्थन करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हाल ही में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अब उसी TVK के साथ गठबंधन कर लिया, जिसने 23 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हराया। उनके मुताबिक, यह महात्मा गांधी के उस सिद्धांत के खिलाफ है जिसमें राजनीति को नैतिकता और सिद्धांतों पर आधारित बताया गया था। समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में अय्यर ने कहा कि "स्वराज नैतिकता पर आधारित होना चाहिए" और कांग्रेस का यह फैसला उस विचारधारा से भटकाव दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में जो पांच सीटें जीतीं, वे उसकी अपनी ताकत से नहीं बल्कि DMK के साथ दशकों पुराने गठबंधन के कारण मिली थीं।

तमिलनाडु में सत्ता का सस्पेंस गहराया

TVK का भविष्य अब वाम दलों और VCK के फैसले पर टिका

तमिलनाडु की राजनीति इस समय पूरी तरह से सस्पेंस और उठापटक के दौर से गुजर रही है। राज्य में सरकार गठन को लेकर हर घंटे नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक ओर अभिनेता-राजनेता थलापति विजय की पार्टी TVK समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगी हुई है, तो दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि वर्षों से एक-दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे DMK और AIADMK भी सत्ता गठन को लेकर बैकडोर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।इस पूरे घटनाक्रम में अब TVK की राजनीतिक दिशा तीन अहम दलों — CPI, CPM और VCK — के फैसले पर निर्भर मानी जा रही है। TVK ने इन तीनों दलों से समर्थन का अनुरोध किया है और सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक इन पार्टियों की ओर से अंतिम निर्णय सामने आ सकता है। इन दलों के भीतर यह राय उभर रही है कि जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए TVK का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ DMK का दबाव भी इन सहयोगी दलों पर माना जा रहा है। गौरतलब है कि CPI, CPM और VCK लंबे समय से DMK गठबंधन का हिस्सा रहे हैं।इसी बीच तमिलनाडु के गवर्नर सी. पी. राधाकृष्णन आर्लेकर के बयान ने भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। चेन्नई में मौजूद गवर्नर ने साफ कहा है कि सरकार गठन के लिए सबसे अहम चीज संख्या बल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस भी दल या गठबंधन के पास 118 विधायकों का समर्थन होगा, उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। गवर्नर की इस टिप्पणी पर TVK और कांग्रेस ने नाराजगी जताई है।वहीं दूसरी तरफ AIADMK प्रमुख ई. पलानीस्वामी ने पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर जुटाए हैं और गवर्नर से मिलने का समय भी मांगा है। उधर DMK नेतृत्व ने अपने सभी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। TVK ने भी आज पनयूर स्थित पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई है।

केरल कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर मंथन तेज

केरल कांग्रेस में नए नेतृत्व और संभावित मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल के बीच शुक्रवार को पार्टी के पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंपेंगे। सूत्रों के अनुसार, यह रिपोर्ट दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली में सौंपी जाएगी। पर्यवेक्षकों ने केरल पहुंचकर कांग्रेस विधायकों के साथ सामूहिक बैठक की थी और बाद में सभी विधायकों से अलग-अलग बातचीत भी की। इन्हीं चर्चाओं और रायशुमारी के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है।सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में के. सी. वेणुगोपाल सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 40 से 43 विधायक उनके समर्थन में हैं, जिससे वे विधायकों की पहली पसंद माने जा रहे हैं। हालांकि, उनके नाम पर अंतिम मुहर लगना अभी आसान नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और पार्टी संगठन में उनकी अहम भूमिका है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी उन्हें दिल्ली की राजनीति से हटाकर केरल की जिम्मेदारी देना चाहेंगे।वहीं अगर किसी कारणवश वेणुगोपाल का नाम आगे नहीं बढ़ता है, तो रमेश चेन्निथला को मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें 20 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अब सभी की नजर कांग्रेस हाईकमान पर टिकी हुई है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व केरल में नए चेहरे और सत्ता संतुलन को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है।

अमेरिकी कोर्ट ने 10% ग्लोबल टैरिफ को किया रद्द

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को एक और बड़ा कानूनी झटका लगा है। न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ (आयात शुल्क) को अवैध और कानून के दायरे से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के कुछ कठोर टैरिफ फैसलों पर रोक लगा चुका है।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया गया, वह राष्ट्रपति को इतनी व्यापक आर्थिक शक्तियां नहीं देता। अदालत ने उन छोटे व्यवसायों के पक्ष में फैसला सुनाया जिन्होंने इस नीति को चुनौती दी थी। हालांकि, पीठ के एक जज ने असहमति जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति को व्यापार और टैरिफ मामलों में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।यह मामला 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लगाए गए अस्थायी 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ से जुड़ा था। ट्रंप प्रशासन ने इन शुल्कों को अमेरिका के व्यापार घाटे को नियंत्रित करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए लागू किया था। ये टैरिफ 24 जुलाई तक प्रभावी रहने वाले थे।इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का हवाला देते हुए अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। इसी आधार पर कई देशों पर व्यापक आयात शुल्क लगाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में साफ कर दिया था कि यह कानून राष्ट्रपति को इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता।

TMC सांसद ने DGCA में दर्ज कराई शिकायत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद राज्य की सियासत अब विमान यात्रा तक पहुंच गई है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि इंडिगो की एक फ्लाइट में कुछ यात्रियों ने उनके खिलाफ अभद्र नारेबाजी की और उन्हें निशाना बनाते हुए व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं। इस घटना को लेकर उन्होंने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है।कृष्णानगर से लोकसभा सांसद मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ वीडियो साझा किए हैं। इन वीडियो में कुछ लोग "चोर-चोर TMC चोर", "तृणमूल ईर शोब चोर" और "जय श्री राम" जैसे नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। मोइत्रा का कहना है कि यह सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि उन्हें जानबूझकर परेशान करने और अपमानित करने की कोशिश थी।उन्होंने आरोप लगाया कि विमान के भीतर उन्हें "मौखिक रूप से प्रताड़ित" किया गया और चूंकि फ्लाइट लैंड होने तक वह वहां से निकल नहीं सकती थीं, इसलिए उनके पास इस स्थिति से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मोइत्रा ने कहा कि यह पूरी घटना सीधे तौर पर उन्हें और उनकी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाकर की गई।TMC सांसद ने एयरलाइन IndiGo से मांग की है कि नारेबाजी करने वाले यात्रियों की पहचान सार्वजनिक की जाए और उन्हें "नो-फ्लाई लिस्ट" में डाला जाए। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को भी टैग करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है।मोइत्रा ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह "BJP की राजनीतिक संस्कृति" को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में उन्होंने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपनी बैठक में चली गईं, लेकिन बाद में जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया। अपनी शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फ्लाइट के दौरान एयरलाइन कर्मचारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने या हस्तक्षेप करने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने इंडिगो स्टाफ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की भी मांग की है। हालांकि, अब तक एयरलाइन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

'सोनार बांग्ला' के लक्ष्य को पूरा करेगी भाजपा: अमित शाह

घुसपैठ और गौ तस्करी पर लगेगी रोक

कोलकाता में अमित शाह ने बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया और जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हिंसा के बावजूद लोगों ने बदलाव चुना। भाजपा सोनार बांग्ला के लक्ष्य के साथ लोकतंत्र, विकास और सीमा सुरक्षा करेगी तथा जनादेश पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत को ऐतिहासिक बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देते हैं, जिनमें बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उभर रहे शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा, धमकियों और दबाव की अनेक घटनाओं के बावजूद बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में मतदान लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहा है। उनके अनुसार, कम्युनिस्ट शासन के दौर से शुरू हुआ भय और राजनीतिक दबाव का माहौल ममता बनर्जी के शासन में और गहरा गया था। ऐसी परिस्थितियों में जनता ने बड़ी संख्या में मतदान कर भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीतिक इतिहास में बदलाव का संकेत है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग पांच दशकों में बंगाल ने लोकतंत्र के क्षरण, कानून-व्यवस्था की कमजोरी, आर्थिक ठहराव और विकास की धीमी रफ्तार को झेला है। अब राज्य एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया जाएगा और विकास को नई दिशा दी जाएगी। अपने भाषण में अमित शाह ने पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल तक भाजपा के विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, असम में भाजपा की सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा ने सत्ता हासिल की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की नई सरकार और केंद्र सरकार मिलकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करेंगी। घुसपैठ और गौ तस्करी जैसी समस्याओं पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और बंगाल की सीमाओं को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले में बदला जाएगा। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से 'सोनार बांग्ला' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब बंगाल उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा उठ सके।शाह ने अपने संबोधन में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस समय देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी थी, लेकिन कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा था कि अभी एक सपना बाकी है—बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना। उन्होंने कहा कि आज वह सपना पूरा हुआ है और उन्हें विश्वास है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां भी होंगे, इस क्षण पर गर्व कर रहे शाह ने भाबानीपुर के मतदाताओं को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें उनके अपने घर में हराया है। उन्होंने कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब बंगाल बदलाव चाहता है और भाजपा उस जनादेश का सम्मान करते हुए राज्य को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत ने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के सत्यापन में तेजी की उम्मीद जताई

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

नई दिल्ली ने कहा कि वह ढाका से भारत से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की वापसी के लिए सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद करती है। वहीं, बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बांग्लादेश सीमा रक्षक बल (बीजीबी) को भारत से किसी भी संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए सीमाओं पर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर ढाका द्वारा अलर्ट जारी करने का यह कदम भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देने के कुछ घंटों बाद आया है। यह पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के बाद हुआ है। ये दोनों भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, और अवैध अप्रवासन का मुद्दा हाल के चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। 5 मई को, विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कहा कि ढाका भारत की ओर से घुसपैठ की घटनाओं के खिलाफ उचित कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अगर किसी भी तरह की घुसपैठ की घटना होती है, तो बांग्लादेश उचित कार्रवाई करेगा। घुसपैठ से रहमान का तात्पर्य उन खबरों से था जिनमें भारत में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा था। ऐसी खबरें आई हैं कि कई राज्यों से अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया और असम और त्रिपुरा से सीमा पार धकेल दिया गया, जहां विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सत्ता में थी। पश्चिम बंगाल अब भाजपा शासित राज्य बनने जा रहा है। रहमान की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि ढाका बंगाल को भी पुश-इन के लिए इस्तेमाल होते हुए देख रहा है। फरवरी 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार को विदेशी घोषित किए गए व्यक्तियों के निर्वासन में तेजी लाने का निर्देश दिया था।

अरविंद केजरीवाल उत्पाद शुल्क मामले में सोमवार को हाईकोर्ट का आदेश

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

अरविंद केजरीवाल उत्पाद शुल्क मामले की सुनवाई की मुख्य बातें: उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सहमति की प्रतीक्षा कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में सोमवार को आदेश पारित किया जाएगा, जबकि सीबीआई द्वारा डिस्चार्ज आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की वैधता पर बहस मंगलवार से शुरू होगी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि न्यायालय एमिकस क्यूरी के रूप में सहायता करने के लिए प्रस्तावित अधिवक्ताओं की सहमति की प्रतीक्षा कर रहा है और उनकी औपचारिक नियुक्ति के लिए मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की, "अब तीन व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहे हैं। मैं उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ एमिकस क्यूरी की सहमति की प्रतीक्षा कर रही हूं। सुनवाई सीबीआई की याचिका की स्वीकार्यता पर कुछ प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में दलीलों के साथ शुरू हुई। इस स्तर पर, न्यायमूर्ति शर्मा ने टिप्पणी की, ठीक है, हम स्वीकार्यता पर सुनवाई करेंगे? सीबीआई की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर दिया, महोदया, यह मेरी याचिका है। मुझे पहले सुना जाना चाहिए। न्यायालय को सूचित किया गया कि स्वीकार्यता संबंधी आपत्तियों के उत्तर पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीश ने दोहराया कि चूंकि केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने मामले में भाग न लेने का विकल्प चुना है, इसलिए न्यायालय ने आगे की बहस से पहले सहायक न्यायाधीशों (अमीकी क्यूरी) की नियुक्ति करना उचित समझा। पीठ ने कहा कि हम इसे सोमवार को रखेंगे।

चीन की सेना में भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार, संपत्ति जब्त और राजनीतिक अधिकार खत्म

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

चीन में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने एक बार फिर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। चीन की सैन्य अदालत ने पूर्व रक्षा मंत्रियों ली शांगफू और वेई फेंघे को रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में दो वर्ष की मोहलत के साथ मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस व्यापक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत सेना, प्रशासन, न्यायपालिका और सरकारी कंपनियों में फैले भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार दोनों नेताओं को आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और उनकी निजी संपत्ति जब्त कर ली गई है। चीन की न्याय व्यवस्था में दो वर्ष की मोहलत वाली मौत की सजा का अर्थ यह है कि यदि दोषी जेल में अच्छा व्यवहार करते हैं तो सजा बाद में बिना पैरोल वाली उम्रकैद में बदली जा सकती है।ली शांगफू वर्ष 2023 में केवल सात महीने तक रक्षा मंत्री रहे थे। इससे पहले वे सेना के उपकरण खरीद विभाग के प्रमुख थे। जांच में उन पर रक्षा सौदों और नियुक्तियों में अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले भारी रिश्वत लेने के आरोप सिद्ध हुए। वहीं वेई फेंघे पांच वर्षों तक रक्षा मंत्री रहे और उससे पहले चीन की रॉकेट फोर्स के प्रमुख थे। उन पर भी बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने और अधिकारियों की नियुक्तियों में पक्षपात करने के आरोप साबित हुए। इन दोनों शीर्ष सैन्य अधिकारियों को दी गई कठोर सजा केवल भ्रष्टाचार विरोधी कदम नहीं, बल्कि सेना पर राजनीतिक नियंत्रण मजबूत करने की रणनीति भी है। वर्ष 2012 में सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया।

ईरान के दिल्ली दौरे से मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई हलचल

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका अचानक वैश्विक चर्चा के केंद्र में आ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी लगातार बढ़ रही है, वहीं इजराइल के हमलों ने पूरे क्षेत्र को और अधिक अस्थिर बना दिया है। इसी माहौल में ईरान के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री के नई दिल्ली आने की खबरों ने पाकिस्तान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार, 14 और 15 मई को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के दोनों वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। भारत इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और सितंबर में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन की तैयारियां भी जारी हैं। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया संकट गहराता जा रहा है, तेहरान का नई दिल्ली की ओर रुख करना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। ईरान उन देशों के साथ रणनीतिक संवाद बढ़ाना चाहता है जो पूरी तरह पश्चिमी दबाव में नहीं हैं। भारत इस समय उसी संतुलित शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। हाल के महीनों में भारत और ईरान के बीच उच्चस्तरीय संपर्क लगातार बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। मार्च में हुई एक अहम वार्ता में ईरान ने स्पष्ट कहा था कि मौजूदा वैश्विक संकट में ब्रिक्स जैसे मंच स्थिरता कायम रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम पहलू पाकिस्तान भी है। हाल में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बैक-चैनल संवाद का माध्यम बनने की कोशिश की थी, लेकिन वह प्रयास आगे नहीं बढ़ सका। दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद ईरान का भारत के साथ उच्चस्तरीय संपर्क बढ़ना इस्लामाबाद के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। नई दिल्ली में होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है।

संपादक की कलम से

वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। मानव जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पर्यावरण संतुलन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आज प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन कटाई और जल संकट जैसी समस्याएँ मानव अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण वायु प्रदूषण और हरितगृह गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन है। कारखानों, वाहनों और बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग ने वातावरण को दूषित कर दिया है। परिणामस्वरूप हिमनद पिघल रहे हैं, मौसम चक्र बदल रहा है और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। यह स्थिति मानव जीवन के साथ-साथ पशु-पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी संकट पैदा कर रही है। वनों की कटाई पर्यावरण असंतुलन का एक बड़ा कारण है। पेड़ न केवल हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ती जनसंख्या और शहरी विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। इससे जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई दुर्लभ जीव-जंतु विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।जल प्रदूषण भी आज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नदियों और तालाबों में औद्योगिक कचरा तथा प्लास्टिक फेंकने से स्वच्छ जल की कमी बढ़ती जा रही है। पीने योग्य पानी का संकट अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि यह आसानी से नष्ट नहीं होता। समुद्री जीव भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए तथा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करके कपड़े और कागज के विकल्प अपनाने चाहिए। जल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देना होगा तथा सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करना चाहिए। विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ सके।

केरल कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल सबसे आगे

47 विधायकों का समर्थन

केसी वेणुगोपाल केरल में कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। 63 में से 47 नवनिर्वाचित विधायकों ने उनके नाम का समर्थन किया है। अंतिम फैसला अब मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कांग्रेस हाईकमान जल्द नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकता है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केरल में कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मंथन निर्णायक चरण में पहुंच गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को एआईसीसी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ हुई व्यक्तिगत बैठकों के दौरान कांग्रेस के 63 नवनिर्वाचित विधायकों में से 47 ने वेणुगोपाल के नाम का समर्थन किया।इन समर्थकों में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, सनी जोसेफ के अलावा संदीप जी वेरियर, सजीव जोसेफ, टी. ओ. मोहन और उषा विजयन समेत कई नवनिर्वाचित विधायकों ने भी वेणुगोपाल को राज्य की कमान सौंपने की वकालत की। इस घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वेणुगोपाल की स्थिति को काफी मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को इस प्रक्रिया में झटका लगा है। उनके करीबी माने जाने वाले विधायक आई. सी. बालकृष्णन ने पर्यवेक्षकों के समक्ष वेणुगोपाल और चेन्निथला दोनों के नाम का समर्थन किया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चेन्निथला को फिलहाल आठ नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन प्राप्त है।वहीं, मौजूदा विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशान, जिन्हें शुरुआत में एक मजबूत और लोकप्रिय दावेदार माना जा रहा था, उन्हें छह विधायकों का समर्थन मिला है। सतीशान और चेन्निथला दोनों ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों से अलग-अलग मुलाकात कर अपनी-अपनी दावेदारी पेश की। दिलचस्प बात यह रही कि केसी वेणुगोपाल स्वयं इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। 63 विधायकों से बातचीत के अलावा केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से भी व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी राय जानी। सूत्रों के अनुसार, जहां केपीसीसी के तीन पूर्व अध्यक्षों ने वी. डी. सतीशान का समर्थन किया, वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने वेणुगोपाल के पक्ष में राय व्यक्त की। पर्यवेक्षक अब नई दिल्ली लौट चुके हैं और जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो पार्टी हाईकमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ, तीनों कार्यकारी अध्यक्षों, वी. डी. सतीशान और रमेश चेन्निथला को आगे की चर्चा के लिए दिल्ली बुला सकता है। इसी बीच, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे को अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया है। इस कदम को नेतृत्व चयन की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।सूत्रों का कहना है कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कांग्रेस हाईकमान शनिवार या रविवार तक केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकता है। इसके बाद नए मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं तथा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों के साथ अगले दो दिनों के भीतर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। कुल मिलाकर, मौजूदा राजनीतिक संकेत स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि केसी वेणुगोपाल फिलहाल मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। हालांकि अंतिम फैसला अब कांग्रेस हाईकमान के हाथों में है, जिस पर पूरे केरल की निगाहें टिकी हुई हैं।

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर तेज हुआ संख्या बल का खेल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

तमिलनाडु की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद तेजी से बदलते घटनाक्रम ने सत्ता गठन को लेकर असमंजस पैदा कर दिया है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के सामने सरकार बनाने की राह आसान नहीं दिख रही। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि टीवीके को सत्ता से दूर रखने के लिए द्रविड़ राजनीति के दो बड़े प्रतिद्वंद्वी दल—डीएमके और एआईएडीएमके—अभूतपूर्व समझौते की दिशा में बढ़ सकते हैं। गुरुवार को विजय ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन टीवीके के पास अभी नहीं है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने विजय से पर्याप्त संख्या बल के साथ दोबारा आने को कहा है। इस संदेश ने राज्य की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है। इसी बीच डीएमके ने तत्काल विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका दी है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन को राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार होगा। इस बयान ने डीएमके और एआईएडीएमके के संभावित गठबंधन की अटकलों को और मजबूत कर दिया। दूसरी ओर एआईएडीएमके के लगभग 40 विधायक पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने विधायकों से एकजुट रहने को कहा है और जल्द किसी सकारात्मक राजनीतिक घटनाक्रम के संकेत दिए हैं। इन घटनाओं से टीवीके में बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी को आशंका है कि राज्यपाल कार्यालय की देरी और द्रविड़ दलों की सक्रियता किसी बड़े राजनीतिक समीकरण का हिस्सा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि यदि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाते हैं तो टीवीके विधायक सामूहिक इस्तीफे जैसे कड़े कदम पर विचार कर सकते हैं।

डीएमके-कांग्रेस गठबंधन टूटने का असर अब संसद में भी दिखा

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने लोकसभा में अपनी राजनीतिक दूरी को औपचारिक रूप देने की पहल की है। डीएमके की लोकसभा सांसद कनिमोझी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में पार्टी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है। यह मांग तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ डीएमके के गठबंधन टूटने के बाद सामने आई है। अपने पत्र में कनिमोझी ने कहा कि बदले हुए राजनीतिक हालात में डीएमके सांसदों का कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठना अब उचित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि डीएमके संसदीय दल के सदस्यों को अलग स्थान दिया जाए ताकि वे सदन में अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। इस कदम को संसद के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। चुनाव में तमिलगा वेट्री कड़गम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस ने उसे समर्थन देकर डीएमके के साथ अपना लंबे समय से चला आ रहा गठबंधन समाप्त कर दिया। पार्टी के संगठन सचिव आर. एस. भारती ने कहा कि डीएमके ने अपने सात दशक से अधिक लंबे इतिहास में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने 1991 के चुनाव का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि उस समय पार्टी 234 में से केवल दो सीटें जीत पाई थी, लेकिन 1996 में जोरदार वापसी कर सत्ता में लौटी थी। आर. एस. भारती ने कहा कि 1991 में दिवंगत वरिष्ठ नेता एम. करुणानिधि हार्बर सीट से और परिथी इलमवझुथी एग्मोर सीट से विजयी हुए थे। उन्होंने कहा कि डीएमके सत्ता से बाहर रहने के बावजूद जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में फिर मजबूत वापसी करेगी।

सिर्फ SAT-GRE नहीं, अमेरिका में एडमिशन दिलाने की असली 'चाबी' है कैपस्टोन प्रोजेक्ट

12वीं के बाद अधिकांश छात्रों का सपना होता है कि वे विदेश में पढ़ाई करें और खासकर अमेरिका जैसे देश में जाकर अपना करियर बनाएं. लेकिन यह सपना सिर्फ अच्छे मार्क्स से पूरा नहीं होता. इसके लिए SAT, ACT (यूजी के लिए), GRE या GMAT (पीजी के लिए) और अंग्रेजी दक्षता के लिए IELTS या TOEFL जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं. हालांकि, अब सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही काफी नहीं है,क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऐसे छात्रों को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी हों. और इसी में सबसे अहम भूमिका निभाता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जो उनकी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करता है. ऐसे में अगर आप भी अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं या बैचलर्स/मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, तो आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए. इसे समझना जरूरी है क्योंकि यह आपकी पढ़ाई की प्लानिंग, प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाने और ग्रेजुएशन के बाद करियर बनाने में काफी मदद करता है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं. कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक ऐसा अकादमिक प्रोजेक्ट होता है, जो किसी कोर्स के अंत में कराया जाता है, जहां एग्जाम के जरिए सिर्फ कोर्स से जुड़ी जानकारी को परखा जाता है और इसका उद्देश्य छात्र की पूरी सीख को एक साथ परखना होता है. यह प्रोजेक्ट यह दिखाता है कि छात्र ने अपने विषय को कितनी गहराई से समझा है और वह उसे वास्तविक जीवन में कैसे लागू कर सकता है. यह प्रोजेक्ट यूजी और पीजी दोनों स्तरों पर अहम होता है. आसान शब्दों में कहें तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट हर डिग्री के लिए जरूरी होता है. यह एक सेमेस्टर या पूरे साल चलने वाला प्रोजेक्ट होता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट केवल थ्योरी तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें रिसर्च, प्रैक्टिकल वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल होती है. यानी छात्र को किसी वास्तविक समस्या पर काम करना होता है और उसका समाधान तैयार करना होता है. कैपस्टोन प्रोजेक्ट के कई प्रकार होते हैं. इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, बिजनेस प्लान, डिजाइन प्रोटोटाइप, केस स्टडी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग के छात्र कोई मशीन या सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, जबकि मैनेजमेंट के छात्र बिजनेस केस स्टडी पर काम करते हैं. वहीं आर्ट्स या मीडिया के छात्र डॉक्यूमेंट्री, फिल्म या कंटेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं. वही प्रोजेक्ट का टाइप चाहे जो भी हो, इसका मुख्य लक्ष्य एक ही रहता है: यह साबित करना कि स्टूडेंट गंभीर रूप से सोच सकता है, जटिल समस्याओं को हल कर सकता है और अपनी फील्ड में प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है. अमेरिका की यूनिवर्सिटीज कैपस्टोन प्रोजेक्ट को खास महत्व देती हैं, क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणाली में प्रैक्टिकल लर्निंग को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रोजेक्ट छात्रों के पोर्टफोलियो का मजबूत हिस्सा बनता है और एडमिशन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. इससे यूनिवर्सिटी को यह समझने में मदद मिलती है कि छात्र सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, बल्कि वह अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया में लागू करने की क्षमता भी रखता है. कैपस्टोन प्रोजेक्ट का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है. इसमें टीमवर्क, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन जैसी स्किल्स विकसित होती हैं. यही स्किल्स आगे चलकर नौकरी पाने में मदद करती हैं. कई बार कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखकर ही छात्रों को इंटर्नशिप या जॉब ऑफर कर देती हैं. वही अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि केवल एग्जाम पास करना ही काफी नहीं है. एक मजबूत कैपस्टोन प्रोजेक्ट आपकी प्रोफाइल को अलग बनाता है और एडमिशन के मौके बढ़ा देता है.

महाराष्ट्र बोर्ड: कुल 92.09 प्रतिशत छात्र-छात्राएं परीक्षा में सफल रहे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज, 8 मई 2026 को कक्षा 10वीं (SSC) के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना परिणाम सीट नंबर और माता के पहले नाम की सहायता से देख सकते हैं। छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट और मार्कशीट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in और sscresult.mahahsscboard.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। बोर्ड अध्यक्ष Trigun Kulkarni के अनुसार, इस बार भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत 94.96% रहा, जबकि लड़कों का कुल पास प्रतिशत 89.56% दर्ज किया गया। रिजल्ट में कोंकण मंडल ने 97.62% पास प्रतिशत के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं छत्रपति संभाजीनगर मंडल 88.41% के साथ सबसे नीचे रहा। इसके अलावा मुंबई का रिजल्ट 94.97%, पुणे 94.24%, कोल्हापुर 95.47%, अमरावती 90.50%, नासिक 90.53% और लातूर 88.42% दर्ज किया गया। महाराष्ट्र कक्षा 10वीं के परिणाम छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइट ही नहीं, बल्कि अन्य वैकल्पिक माध्यमों से भी देख सकते हैं। विद्यार्थी sscresult.mkcl.org, mahahsscboard.in और results.gov.in जैसी वेबसाइटों पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल लॉकर और एसएमएस सेवा के माध्यम से भी स्कोरकार्ड प्राप्त किया जा सकता है। जो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उन्हें पहले उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी लेना जरूरी होगा। फोटोकॉपी मिलने की तारीख से पांच कार्यदिवस के भीतर छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट Maha HSSC Board पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा करके करना होगा।

विराट कोहली को उनकी पहली ही गेंद पर आउट करने के बाद प्रिंस यादव जश्न मानते हुए

चर्चा आज हर क्रिकेट फैन की जुबान पर तेज गेंदबाज प्रिंस यादव

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अगर किसी एक गेंदबाज के नाम की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, तो वह हैं लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव। गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में प्रिंस ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसकी चर्चा आज हर क्रिकेट फैन की जुबान पर है। उन्होंने किंग विराट कोहली को शून्य (0) पर आउट कर सनसनी मचा दी। आरसीबी के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य था। उम्मीद थी कि विराट कोहली क्रीज पर टिककर मैच जिताएंगे, लेकिन प्रिंस यादव के इरादे कुछ और ही थे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए प्रिंस ने अपनी दूसरी ही गेंद पर विराट को चारों खाने चित कर दिया। गेंद की मूवमेंट इतनी शानदार थी कि विराट का विकेट उड़ गया और वह खुद हैरान रह गए। बता दें कि साल 2017 के बाद विराट कोहली पहली बार आईपीएल में बिना खाता खोले आउट हुए हैं। मैच के बाद जब प्रिंस यादव से पूछा गया कि उन्होंने विराट कोहली जैसे दिग्गज को कैसे फंसाया, तो उन्होंने एक बड़ा राज़ खोला। प्रिंस ने बताया, 'पिछले मैच के बाद मेरी विराट भैया से बात हुई थी। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे सलाह दी थी कि 'जिस लेंथ पर तुम्हें मदद मिल रही है, बस उसी पर टिके रहो और गेंदबाजी करते रहो।' मैंने उनकी वही बात गांठ बांध ली और आज उन्हीं के खिलाफ उसी लेंथ पर गेंद डाली।' प्रिंस ने इस मैच में सिर्फ विराट का ही नहीं, बल्कि देवदत्त पड्डिकल और जितेश शर्मा का भी विकेट चटकाया। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। प्रिंस की इसी गेंदबाजी की बदौलत आरसीबी 203 रन ही बना सकी और लखनऊ ने यह रोमांचक मुकाबला 9 रन से जीत लिया।

नजमुल हुसैन शांतो ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त शतक लगाया

बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने पाकिस्तान की जमकर खबर ली। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला पहले तो लगा कि शान मसूद ने ठीक किया है, लेकिन नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार सैकड़ा जड़कर विरोधी टीम को शांत कर दिया। एक वक्त संकट में नजर आ रही बांग्लादेशी टीम को उन्होंने मुश्किल से निकालकर एक ठीकठाक स्थिति में पहुंचा दिया है। बांग्लादेश ने 200 से अधिक रन बना लिए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने शुक्रवार सुबह टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दो विकेट पाकिस्तान के जल्दी गिर गए थे। जब टीम का स्कोर केवल 31 रन था, तब तक दो विकेट गिर चुके थे। इसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और मोमिनुल हक ने मोर्चा संभाला। शांतो ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और टेस्ट शतक पूरा किया। उन्होंने 130 बॉल पर 101 रन बनाए और शतक पूरा करने के तुरंत बाद आउट हो गए। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौक और दो छक्के आए। नजमुल हुसैन शांतो का पाकिस्तान के खिलाफ ये पहला टेस्ट शतक है, इससे पहले वे शतक तो दूर की बात है, अर्धशतक तक नहीं लगा पाए थे, लेकिन आज उन्होंने सेंचुरी ठोक ही दी। शांतो ने अपने करियर में अब तक 39 मैच खेलकर दो हजार से अधिक रन बनाए हैं। इसमें 9 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी ओर मोमिनुल हक ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर 150 से अधिक रनों की साझेदारी की। उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है और अभी नाबाद हैं।

बिहार-झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्सदाता बने धोनी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं बल्कि टैक्स भुगतान है। आयकर विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड और बिहार क्षेत्र में धोनी सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्सदाता रहे। यह जानकारी आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) डॉ. डी. सुधाकर राव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दी। डॉ. राव ने बताया कि बिहार और झारखंड से कुल टैक्स संग्रह लगभग 20,000 करोड़ रुपये रहा। इसमें सबसे बड़ा योगदान झारखंड का रहा। उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार और झारखंड से कुल लगभग 20,000 करोड़ रुपये टैक्स संग्रह हुआ, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपये सिर्फ झारखंड से प्राप्त हुए।' उन्होंने यह भी बताया कि कुल टैक्स संग्रह का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के जरिए आया। जब सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्सदाता का नाम पूछा गया तो डॉ. राव ने साफ तौर पर धोनी का नाम लिया। उन्होंने कहा, 'पिछले वित्त वर्ष में बिहार और झारखंड को मिलाकर एमएस धोनी सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्सदाता रहे।' हालांकि उन्होंने धोनी द्वारा चुकाई गई टैक्स राशि का खुलासा नहीं किया। कॉरपोरेट श्रेणी में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और सीएमपीडीआई सबसे बड़े टैक्सदाताओं में शामिल रहे। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले साल भारी बारिश के कारण खनन गतिविधियों पर असर पड़ा, जिससे टैक्स संग्रह भी प्रभावित हुआ। डॉ. राव ने कहा, 'पिछले वित्त वर्ष में भारी बारिश के कारण माइनिंग गतिविधियां प्रभावित हुईं। हमें उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करेंगे।' डॉ. राव ने आयकर अधिकारियों के साथ नए आयकर अधिनियम 2025 पर बैठक भी की। यह नया कानून 1 अप्रैल से लागू होगा और 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। उन्होंने कहा, 'नया कानून सरल भाषा, सुव्यवस्थित ढांचे और आसान प्रस्तुति के जरिए अनुपालन को और सरल बनाएगा।'

बार की शर्त देख आप भी वहां जाना चाहेंगे

जूते दो बीयर लो

इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बार का अनोखा चैलेंज दिखाया गया है. यहां जूते लेकर बीयर की मग दी जाती है. मग भी ऐसा अजीबोगरीब है कि उसे टेबल पर रखना मुश्किल है.

सोशल मीडिया पर कई ऐसी नई-नई चीजें वायरल होती रहती हैं, जिन्हें हमने पहले कभी न देखा है, न अनुभव किया है. कुछ ऐसा ही विदेश घूमने गई भारत की एक लड़की ने अपने वीडियो में दिखाया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

इंस्टाग्राम पर @chahat_anand नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो का कैप्शन है - मैं गिलास को टेबल पर रख ही नहीं पाई और उस भारी गिलास को ठीक बीच में से बाहर निकालना भी मुश्किल था. मुझे बेल्जियम के Ghent में यह एक बहुत ही मजेदार अनुभव था.

इस वीडियो में दिखाया गया है कि भारत की एक लड़की बेल्जियम के एक बार में बैठी हुई है. तभी वहां एक स्टाफ आता है. वह लड़की से उसके एक जूते लेकर चला जाता है. फिर उसे एक बड़े से बीकर जैसे मग में बीयर लाकर देता है. उस बीकर का बॉटम कर्व होता है. इस वजह से उसे टेबल पर रखना मुश्किल है. अगर बीयर पीते हुए भूल से भी उस बीयर मग को टेबल पर टिकाने की कोशिश करने पर वह गिर सकता है. उस अजीबोगरीब बीयर मग में 1.2 लीटर बीयर भरा था. लड़की ने सही सलामत जब उस मग से पूरी बीयर खत्म कर ली, तब जाकर फिर से वो स्टाफ आया और उसके हाथ से वो बड़ा सा बीयर मग लेकर चला गया. इसके बाद उसे उसका एक जूता दे दिया गया.

इस बार में बैठकर बीयर पीने का चैलेंज पूरा करना है मुश्किल (Photo - Instagram/@chahat_anand)

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उस बार में स्टाफ लोगों से एक जूते बीयर चैलेंज पूरा करने के इश्योरेंस के तौर पर लेते हैं. जब बीयर पीने के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं होती तो लोगों को उनका एक जूता लौटा दिया जाता है.

अचानक चलती कार से कूदी महिला

मलेशिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने डर के कारण चलती टैक्सी से छलांग लगा दी. यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 1 मई की सुबह एक व्यस्त हाईवे पर हुई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अचानक कार का दरवाजा खोलती है और चलती गाड़ी से सड़क पर कूद जाती है. गिरते ही उसके जूते और मोबाइल सड़क पर बिखर जाते हैं, जबकि आसपास चल रही गाड़ियां अचानक ब्रेक लगाती हैं.

घोंघों की रेस ने खींचा दुनिया का ध्यान

स्लो लाइफ को सेलिब्रेट करता है ताइवानी शहर

दुनिया जहां तेज भागदौड़ से भरी है, वहीं कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. आखिर इतनी भागदौड़ क्यों? क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ तेजी है? क्या कुछ काम धीरे नहीं हो सकते? इसी सोच और फिलॉसफी पर ताइवान के हुलिएन काउंटी में बसा छोटा सा शहर फेंगलिन चलता है. इस शहर में लोग तेज रफ्तार जिंदगी नहीं, बल्कि धीमी और संतुलित जीवनशैली को सेलिब्रेट करते हैं. यही वजह है कि यहां आयोजित

होने वाली अनोखी घोंघा रेस अब पूरे ताइवान में चर्चा का विषय बन गई है. घोंघा, जिसकी रफ्तार बेहद धीमी होती है, यहां की पहचान बन चुका है.

पहले ही हो गई थी CM बनने की भविष्यवाणी

विजय की कार का नंबर वायरल!

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में इस बार विजय थलापति का जादू सिर चढ़कर बोला. उनकी पार्टी का प्रदर्शन ऐसा रहा कि अच्छे- अच्छे दिग्गज चित हो गए.

मुख्यधारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, हर तरफ विजय का ही जलवा है. ऐसे में इंटरनेट पर उनकी जीत से जोड़कर विजय के कई पुराने- नए फिल्मों के क्लिप भी वायरल हो रहे हैं. इनमें से सबसे खास वीडियो क्लिप उनकी GOAT नाम की फिल्म का है. इस फिल्म का वायरल हो रहा क्लिप क्यों

खास है, वह इसे देखकर पता चल जाएगा. विजय की 2024 में आई फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम GOAT के इस वीडियो क्लिप में विजय एक कार पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. उस कार का नंबर है - 'TN 07 CM 2026'. वैसे तो यह वीडियो तब से वायरल है, जब उनकी पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू किया था. अब जब उन्होंने चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल की है और उनके सीएम बनना पक्का हो गया है.

'राजा शिवाजी' रिव्यू: भव्यता, भावनाओं और शिवराय के गौरव से भरी लेकिन बिखरी हुई कहानी

मुख्य भूमिका में रितेश देशमुख ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ दृश्यों में उनकी सादगी और कुछ में उनका रौद्र रूप प्रभावित करता है। हालांकि कहीं-कहीं वे अपनी पुरानी फिल्म 'लय भारी' वाले अंदाज में नजर आते हैं, जो महाराज के किरदार की गरिमा के साथ थोड़ा विरोधाभास पैदा करता है। फिर भी एक्शन सीक्वेंस और स्लो-मोशन शॉट्स में वे काफी जचते हैं। जेनेलिया डिसूजा ने महारानी सईबाई का किरदार निभाया है, लेकिन उनके मराठी लहजे में अभी भी वह सहजता नहीं आ पाई है जो इस तरह के ऐतिहासिक पात्र के लिए अनिवार्य थी। विद्या बालन जैसी दिग्गज अभिनेत्री को फिल्म में बहुत कम मौका मिला है, जिससे उनके प्रशंसकों को थोड़ी निराशा हो सकती है। उनके चेहरे के भाव कई बार टीवी सीरियल्स की याद दिलाते हैं। संजय दत्त ने अफजल खान के रूप में शानदार काम किया है। उनकी कद-काठी और दमदार आवाज ने अफजल खान के खौफ को पर्दे पर बखूबी उतारा है। अभिषेक बच्चन का कैमियो और मराठी संवाद सुनने में थोड़े असहज लगते हैं, जबकि फरदीन खान का किरदार बिना किसी खास प्रभाव के शुरू और खत्म हो जाता है। सचिन खेडेकर और भाग्यश्री जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अपने अनुभव से फिल्म को सहारा दिया है। अंत में सलमान खान की धमाकेदार मौजूदगी फिल्म की स्टार पावर में चार चांद लगा देती है। 'राजा शिवाजी' की सबसे बड़ी समस्या इसकी लंबाई और एडिटिंग है। तीन घंटे से अधिक की यह फिल्म कई जगहों पर खिंची हुई महसूस होती है। फिल्म की गति ऊपर-नीचे होती रहती है, जिससे दर्शक कई बार बेचैन हो सकते हैं। पटकथा में निरंतरता की कमी है, एक सीन से दूसरे सीन पर जाने में वो सहजता नहीं है जो एक विश्वस्तरीय ऐतिहासिक ड्रामा में होनी चाहिए। एक्शन दृश्यों में तर्क की तलाश करना व्यर्थ है, लेकिन उनमें एक सुसंगत ढांचा होना चाहिए था, जिसकी यहां कमी खलती है। फिल्म का कुछ हिस्सा तकनीक के मामले में बहुत आधुनिक लगता है तो कुछ हिस्सा बहुत पुराना। यह असंतुलन फिल्म के समग्र प्रभाव को थोड़ा हल्का कर देता है। 'राजा शिवाजी' एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि अपने दिल से देखते हैं। इसमें खामियां हैं, यह कहीं-कहीं बचकानी भी लगती है और संपादन के मामले में कच्ची भी है। लेकिन, जब पर्दे पर भगवा परचम लहराता है और महाराज का जयघोष होता है, तो सारी शिकायतें गौण हो जाती हैं। फिल्म का आखिरी 20 मिनट का क्लाइमेक्स और महाराज का अदम्य साहस दर्शकों को अपनी सीटों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देता है। रितेश देशमुख ने अपनी क्षमता के अनुसार एक भव्य श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है, जो व्यावसायिक रूप से सफल साबित होगी। यह फिल्म सिनेमाई बारीकियों के लिए नहीं, बल्कि उस गौरव और गर्व के लिए देखी जानी चाहिए जो हमें अपने इतिहास पर है। यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं, तो आप इस फिल्म के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। सिनेमाई कमियों के बावजूद, 'शिवराय' का नाम ही इस फिल्म को देखने के लिए पर्याप्त कारण है। 'राजा शिवाजी' एक भव्य मगर थोड़ी बिखरी हुई फिल्म है। यह महाराज के प्रति रितेश देशमुख का प्रेम और श्रद्धा है जो इस फिल्म को डूबने से बचा लेती है। इसे केवल उस 'पीक शिवराय-इज्म' के लिए देखें जो अंत में आपको एक अलग ही रोमांच से भर देगा।

लखनऊ में चुनाव आयोग के घेराव पर सपा कार्यकर्ता हिरासत में

लखनऊ में चुनाव आयोग के घेराव के लिए निकले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बापू भवन के पास रोककर हिरासत में ले लिया। धक्का-मुक्की में कई कार्यकर्ताओं के कपड़े फट गए। चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी हुई और प्रदर्शन के कारण आसपास कुछ देर यातायात भी प्रभावित रहा।

लखनऊ में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन उस समय तीखा हो गया जब पुलिस ने उन्हें बापू भवन के पास रोककर हिरासत में ले लिया। पार्टी कार्यकर्ता चुनाव आयोग के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया था। इसके बाद मौके पर स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच जोरदार धक्का-मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे थे। कई कार्यकर्ताओं के हाथों में 'लोकतंत्र निशाने पर' लिखी तख्तियां थीं, जबकि कुछ लोग पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें भी लिए हुए थे। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। "चुनाव आयोग मुर्दाबाद" और "लोकतंत्र बचाओ" जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। जैसे ही प्रदर्शनकारी बापू भवन की ओर बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की तेज हो गई। हालात ऐसे बन गए कि कई कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फट गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया और कई कार्यकर्ताओं को जबरन पुलिस वाहनों में बैठाकर हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवेश यादव और प्रकाश मौर्य ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था की तरह काम नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि आयोग लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के बजाय लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने कठोर व्यवहार किया और उन्हें जबरन गाड़ियों में बैठाया गया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने हालात को नियंत्रण में रखने के लिए बापू भवन और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया था। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। आसपास के मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और कुछ जगहों पर जाम जैसी स्थिति बन गई। समाजवादी पार्टी का यह प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ बढ़ते असंतोष को लेकर किया गया था। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदर्शन ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सका, लेकिन इस घटनाक्रम ने राजधानी लखनऊ में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

लखनऊ के बीकेटी में तेज रफ्तार कार ने मामा भांजे को मारी टक्कर

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार मामा-भांजे को टक्कर मार दी। हादसे में मामा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान कल्याणपुर निवासी रामू कुमार (45) कुमार के रूप में हुई। वह अपने भांजे विजय के साथ गुरुवार रात किसान पथ के पास स्थित एक लॉन से काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहे थे। दोनों वेटर का काम करते थे। तड़के करीब 3 बजे बीकेटी इलाके में किसान पथ के पास पीछे से तेज रफ्तार कार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रामू कुमार सड़क पर दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भांजा विजय उछलकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक रामू कुमार की पत्नी का नाम रामा है। परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके। बीकेटी पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

12 मई को नगर निगम चलाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ जिला कोर्ट परिसर के आसपास वकीलों के वो चैंबर हटाए जाएंगे, जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। नगर निगम ने ऐसे 72 अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि तय तारीख 12 मई को नगर निगम ऐसे चैंबरों को अभियान चलाकर हटाए। इसके लिए प्रशासन पुलिस बल उपलब्ध कराएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध कब्जों से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है, इसलिए इन्हें हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट में लखनऊ नगर निगम की ओर से दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि कोर्ट क्षेत्र में 72 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। इनमें अधिकांश वकीलों के चैंबर हैं। कुछ दुकानें भी हैं। अदालत ने इससे पहले भी नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, पुलिस बल पर्याप्त न होने पर कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने डीसीपी मुख्यालय, डीसीपी पश्चिम और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिमी के पत्र अदालत में पेश किए। इन पत्रों में बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित तारीख पर नगर निगम को पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमण

हटाने के लिए अब 12 मई की नई तारीख तय की गई है। खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण 25 अप्रैल को पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन अगली निर्धारित तिथि पर नगर निगम को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि अवैध निर्माण और कब्जे हटाए जा सकें। अदालत ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई पूरी

IRCTC लखनऊ ने लॉन्च किया समर स्पेशल टूर पैकेज

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

IRCTC लखनऊ ने गर्मी की छुट्टियों के लिए धर्मशाला-खज्जियार विद शक्तिपीठ के लिए समर स्पेशल टूर पैकेज लॉन्च किया है। यह पैकेज 6 रात और 7 दिन का होगा। इसमें यात्रियों को हिमाचल प्रदेश के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। IRCTC के अनुसार, यात्रा के दौरान यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था अच्छे होटलों में की जाएगी। पैकेज में नाश्ता और रात का खाना, स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थलों का टूर और टूर एस्कॉर्ट की सुविधा शामिल रहेगी। टूर के दौरान यात्रियों को अमृतसर का अटारी-वाघा बॉर्डर और स्वर्ण मंदिर, खज्जियार की झील और घास के मैदान, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर और भूरी सिंह संग्रहालय दिखाया जाएगा। इसके अलावा धर्मशाला का HPCA क्रिकेट स्टेडियम, मैक्लोडगंज का भगसूनाग मंदिर और दलाई लामा मंदिर भी यात्रा में शामिल हैं। श्रद्धालुओं को चामुंडा देवी और श्री बज्रेश्वरी देवी शक्तिपीठ के दर्शन भी कराए जाएंगे। एक व्यक्ति के रुकने पर पैकेज 69,800 रुपए होगा। दो लोगों के साथ रुकने पर प्रति व्यक्ति 53,500 रुपए और तीन लोगों के साथ ठहरने पर 50,200 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे।

भरोसा जीतकर सोने के झुमके और लॉकेट लेकर फरार हुआ आरोपी

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार इलाके में एक शातिर युवक ने बीमारी का बहाना बनाकर सर्राफा कारोबारी से जेवर लेकर भाग गया। आरोपी खुद को टीबी का मरीज बताकर हर बार मास्क लगाकर दुकान पहुंचता था। तीन दिन तक दुकान पर आकर भरोसा जीतने के बाद वह सोने के झुमके और लॉकेट झपटकर फरार हो गया। भोला चौराहा छोटा भरवारा निवासी मुन्ना कुमार विज्ञान खंड में मंगलम ज्वेलरी नाम से दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक युवक ने फोन कर अपनी पत्नी के टूटे झुमके और लॉकेट बदलवाने की बात कही थी। कारोबारी ने उसे अगले दिन आने को कहा, लेकिन वह उसी शाम दुकान पहुंच गया। इसके बाद आरोपी लगातार तीन दिन तक दुकान पर आता रहा। कभी झुमकों के डिजाइन देखता तो कभी लॉकेट पसंद करने की बात करता। छोटे कारोबारी होने के कारण दुकान पर मनचाहा सामान उपलब्ध नहीं था, इसलिए दुकानदार उसे अगले दिन आने को कहता रहा। गुरुवार दोपहर आरोपी ने फिर फोन कर पूछा कि सामान तैयार हो गया है या नहीं। शाम करीब सात बजे वह मास्क लगाकर दुकान पहुंचा। दुकानदार ने मास्क के बारे में पूछा तो उसने खुद को टीबी का मरीज बताते हुए सावधानी के लिए मास्क पहनने की बात कही।

लखनऊ में कौशल किशोर और जयदेवी के खिलाफ सड़कों पर उतरा अर्कवंशी समाज

लखनऊ में पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर और विधायक जयदेवी के खिलाफ अर्कवंशी समाज सड़क पर उतर आए हैं। मलिहाबाद में शुक्रवार को अर्कवंशी समाज के करीब हजार लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम अंकित कुमार को ज्ञापन सौंपा । उनका कहना है कि मलिहाबाद में जो मल्हिया पासी गेट लगाया गया है। वह उनके समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लगाया गया है। यह विवाद 22 तारीख को मल्हिया पासी स्मृति द्वार हटाए जाने के बाद शुरू हुआ। आरोप है कि इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल और उनकी पत्नी ने वहां नया बोर्ड लगवाया। अखिल भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट ने कहा है कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा। संगठन ने विधायक जय देवी और उनके पति कौशल किशोर पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। मलिहाबाद में मल्हिया पासी नामक स्मृति द्वार बनवाकर इतिहास को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। महासंघ का मानना है कि यह महाराजा मल्हिय सिंह अर्कवंशी की ऐतिहासिक पहचान को मिटाने का प्रयास है, जिससे पूरे अर्कवंशी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। अर्कवंशी समाज के पदाधिकारियों ने लखनऊ के जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। उनकी प्रमुख मांगें हैं कि विवादित स्मृति द्वार को तत्काल हटाया जाए और महाराजा मल्हिय सिंह अर्कवंशी के सही नाम तथा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एक नया भव्य स्मृति द्वार स्थापित किया जाए। महासंघ के अध्यक्ष ओ.पी. सिंह अर्कवंशी ने कहा, यह केवल एक गेट का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे गौरवशाली इतिहास, सम्मान और पहचान की लड़ाई है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया, तो अर्कवंशी समाज शांत नहीं बैठेगा। आने वाले दिनों में प्रदेश भर में धरना-प्रदर्शन और व्यापक आंदोलन की तैयारी की जा रही है।

उन्नाव में 2267 करोड़ रुपये की सड़क और सेतु परियोजनाओं को मिली रफ्तार

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में सड़क और सेतु निर्माण कार्यों को नई गति देने के उद्देश्य से शुक्रवार को विकास भवन सभागार में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने की। इसमें जनप्रतिनिधियों, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में प्रस्तावित सड़क, सेतु और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें अंतिम रूप देना था। लोक निर्माण विभाग की ओर से बैठक में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर यह योजना तैयार की गई है। इस वार्षिक कार्ययोजना के तहत कुल 2267.46 करोड़ रुपये की लागत से 1500.453 किलोमीटर लंबाई के 789 विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सेतु निर्माण, रोड सेफ्टी से जुड़े कार्य, हेलिपैड तथा भवन निर्माण जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। कार्ययोजना के अनुसार विधानसभा पुरवा क्षेत्र में सबसे अधिक 643.96 करोड़ रुपये की लागत से 373.007 किलोमीटर लंबाई के 159 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। विधानसभा भगवंतनगर के लिए 279.86 करोड़ रुपये की लागत से 260.266 किलोमीटर लंबाई के 143 कार्य शामिल किए गए हैं। इसी तरह विधानसभा उन्नाव क्षेत्र में 263.83 करोड़ रुपये की लागत से 194.605 किलोमीटर लंबाई के 132 कार्य

प्रस्तावित हैं। विधानसभा मोहान के लिए 484.19 करोड़ रुपये की लागत से 234.087 किलोमीटर लंबाई के 91 कार्यों को कार्ययोजना में स्थान दिया गया है। वहीं विधानसभा बांगरमऊ क्षेत्र में 365.45 करोड़ रुपये की लागत से 233.811 किलोमीटर लंबाई के 143 विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। विधानसभा सफीपुर के लिए 230.14 करोड़ रुपये की लागत से 204.677 किलोमीटर लंबाई के 121 कार्य योजना का हिस्सा बनाए गए हैं। बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड ने बताया कि इस योजना में जिले की मौजूदा जरूरतों और भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्ययोजना को जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद विभाग प्रत्येक परियोजना का विस्तृत स्टीमेट तैयार करेगा और वित्तीय मंजूरी प्राप्त होने पर निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावों की प्राथमिकता तय कर आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि शासन से स्वीकृति मिलते ही विकास कार्यों को तेजी से शुरू कराया जाए ताकि जनता को बेहतर सड़क, सुरक्षित यातायात और मजबूत बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके। बैठक में विधायक बंबा लाल दिवाकर, अनिल सिंह, श्रीकांत कटियार तथा विधान परिषद सदस्य अरूण पाठक सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि इस कार्ययोजना के लागू होने से उन्नाव के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवागमन की स्थिति बेहतर होगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

पुरवा तहसील में सरकारी भूमि पर बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

जिलाधिकारी के निर्देश पर पुरवा तहसील प्रशासन ने सरकारी भूमि और तालाब पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दो स्थानों पर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त कर लगभग 60 लाख रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान राजस्व और पुलिस विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पहला मामला तहसील पुरवा के ग्राम अकोहरी, परगना मौरावां का है। यहां गाटा संख्या 395, जो राजस्व अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, उसके 0.013 हेक्टेयर हिस्से पर सुभाष चंद्र ने अवैध कब्जा कर लिया था। यह भूमि मौरावां-अकोहरी-गुरबक्शगंज मुख्य मार्ग के किनारे स्थित है। आरोप है कि सुभाष चंद्र ने भूमि पर पिलर गाड़कर अतिक्रमण किया था। प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस और मौखिक निर्देश दिए जाने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद छह मई को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर भूमि को कब्जामुक्त कराया। दूसरा मामला भी ग्राम अकोहरी से संबंधित है। यहां गाटा संख्या 5332, जो अभिलेखों में तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है और जिसका कुल रकबा 0.948 हेक्टेयर है, उसके 0.013 हेक्टेयर हिस्से पर राजेश पुत्र प्रेमनाथ निवासी पठई मजरा अकोहरी द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था। आरोपी ने पिलर और दीवार खड़ी कर तालाब की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। प्रशासन ने निर्माण रोकने के कई निर्देश दिए, लेकिन कार्य जारी रहा। छह मई को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को गिरवा दिया और तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

भागवत श्रवण से मनुष्य के जीवन में प्रेम शांति और सदाचार का संचार होता है: उपेंद्रनाथ चतुर्वेदी

टीवी भारतवर्ष हाथरस

हाथरस। आगरा रोड स्थित शिव कॉलोनी के राधा विद्या मंदिर परिसर में श्री निकुंज बिहारी राधा माधव की असीम अनुकंपा से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथा का वाचन वैष्णवाचार्य परम पूज्य उपेंद्रनाथ चतुर्वेदी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। कथा परीक्षित एवं संयोजक की भूमिका महेश तिवारी एवं रजनी वाला द्वारा निभाई जा रही है।कथा के दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं कासगंज कोऑर्डिनेटर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने पहुंचकर श्रीमद्भागवत कथा का रसपान किया तथा भागवताचार्य उपेंद्रनाथ चतुर्वेदी महाराज को पीत वस्त्र उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान कार्यक्रम में पंडित अविनाश चंद्र पचौरी, पंडित जयशंकर पाराशर, कपिल नरूला आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कथा की व्यवस्थाएं श्री कृष्णा गौतम द्वारा संभाली जा रही हैं।इस अवसर पर भागवताचार्य उपेंद्रनाथ चतुर्वेदी महाराज ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानव जीवन को सत्य, सेवा, संस्कार और सदाचार की ओर प्रेरित करने वाला दिव्य ज्ञान यज्ञ है। उन्होंने कहा कि जब-जब समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है तब भगवान की कथाएं मनुष्य को धर्म और मानवता का मार्ग दिखाती हैं। भागवत श्रवण से मन की अशांति समाप्त होती है तथा व्यक्ति के जीवन में प्रेम, करूणा और भक्ति का संचार होता है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया। वहीं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों की जीवंत धरोहर है। वर्तमान समय में समाज को आध्यात्मिक चेतना, नैतिक संस्कार और आपसी सद्भाव की सबसे अधिक आवश्यकता है, जिसका संदेश भागवत कथा देती है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से परिचित कराते हैं। उन्होंने कथा आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि धर्म और संस्कृति के संरक्षण हेतु इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए। कथा श्रवण करने वालों में नित्यानंद शर्मा, केडी शर्मा, हरिश्चंद्र, विनोद शुक्ला, गंगासहाय उपाध्याय, शशि शर्मा, बलबीर सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु कथा का आनंद ले रहे हैं।

डीआरएम सुनील कुमार वर्मा को निरीक्षण में मिलीं गंभीर तकनीकी खामियां

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में कानपुर-लखनऊ रेल मार्ग पर स्थित छमकनाली 108 पुलिया के पुनर्निर्माण कार्य को रेलवे प्रशासन ने रोक दिया है। प्रस्तावित पैनल शिफ्टिंग और नए स्ट्रक्चर की स्थापना का काम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा को निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में गंभीर तकनीकी खामियां मिली थीं, जिसके बाद उन्होंने कार्यदायी संस्था को सुधार के निर्देश दिए। यह छमकनाली 108 पुलिया ब्रिटिश काल की बनी हुई है और लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी। रेलवे इसे बदलने के लिए कई दिनों से निर्माण कार्य करा रहा था। कार्यदायी संस्था स्वास्तिक एंड कंपनी ने पुलिया का नया स्ट्रक्चर तैयार किया था। गंगा नदी पर बने रेलवे पुल पर एच-बीम चैनल स्लीपर डालने के लिए एक मेगा ब्लॉक लिया गया था, इसी दौरान इस स्ट्रक्चर की पैनल शिफ्टिंग की जानी थी। डीआरएम सुनील कुमार वर्मा सड़क मार्ग से गंगाघाट स्टेशन पहुंचे। वहां से उन्होंने अपनी कार छोड़कर पुश ट्रॉली से छमकनाली 108 पुलिया तक जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें कार्यदायी संस्था के काम में कई तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी खामियां मिलीं। इसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से शिफ्टिंग का कार्य रुकवा दिया। डीआरएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी तकनीकी खामियां दूर किए बिना पुलिया का कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि रेलवे किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा। सभी मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, अब कार्यदायी संस्था को संशोधित निर्देशों के अनुसार स्ट्रक्चर में सुधार करना होगा। इस बीच, बैराज मार्ग स्थित सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर भी रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डिप्टी चीफ इंजीनियर ब्रिज आशीष कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि 30 मई से ब्लॉक लेकर गार्डर रखने का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लॉक मिलते ही तेजी से कार्य कराया जाएगा और चार दिनों के भीतर 108 पुलिया को बदलने का लक्ष्य रखा गया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सरैया रेलवे क्रॉसिंग का भी जायजा लिया और गेटमैन से आवश्यक जानकारी प्राप्त की।

बुजुर्ग दंपति की फरियाद सुन डीएम पहुंचे जिला पूर्ति कार्यालय

टीवी भारतवर्ष हाथरस

हाथरस। जनपद में शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए पहचाने जाने वाले जिलाधिकारी अतुल वत्स की शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान बड़ी कार्रवाई देखने को मिली।जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग दंपति अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचा। दंपति ने बताया कि वह लंबे समय से अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनका राशन कार्ड नहीं बनाया गया। बुजुर्ग दंपति की समस्या सुनते ही जिलाधिकारी अतुल वत्स तत्काल उन्हें अपने साथ लेकर जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंच गए। वहां उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव राज यादव को पीड़ित दंपति का अंत्योदय राशन कार्ड जल्द बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में मिली खामियों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए।

फांसी लगाकर राजमिस्त्री ने की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम

हाथरस। कोतवाली सदर क्षेत्र के नगला बेरिया में एक राजमिस्त्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय जितेंद्र पुत्र रामचरण निवासी नगला बेरिया के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, जितेंद्र की बड़ी बेटी को गांव का ही एक शादीशुदा युवक लंबे समय से परेशान और शोषित कर रहा था। आरोपी युवक द्वारा युवती को धमकियां भी दी जा रही थीं, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक, उसके परिवार के सदस्य और कुछ अन्य लोग लगातार जितेंद्र को धमका रहे थे। इन धमकियों से वह काफी मानसिक तनाव और भय में रहने लगा था। बताया गया कि इसी तनाव के चलते देर रात उसने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है तथा तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाह डॉक्टरों पर गाज गिरी अपर मुख्य सचिव को कार्रवाई के दिए निर्देश

डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव को चिकित्सकीय कार्यों एवं अपने कर्तव्य दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच में आरोप सही पाए गए। लिहाजा उनकी दो वेतनवृद्धियां रोक दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश में लापरवाह डॉक्टरों पर एक्शन लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बर्खास्तगी, तबादले और वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं। डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जनसेवा के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही एवं अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड जांच सेंटर के पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया में खेल करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। अम्बेडकर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार शैवाल एवं डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय वर्मा पर निजी अस्पतालों के पंजीकरण व नवीनीकरण में अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है। निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउण्ड जांच सेन्टरों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रकिया में जानबूझ कर अनियमितता किए जाने, शासनादेशों के उल्लंघन करने और फाइलों को स्वीकृत किये जाने में लापरवाही बरती गई। उक्त चिकित्साधिकारियों ने अपने पद का दुरूपयोग किया। शिकायत के बाद एडीएम सहित तीन सदस्यीय कमेटी ने मामले की जांच की। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के प्रति कड़ा रुख अख्तियार किया। अपर मुख्य सचिव को दोनों डॉक्टरों पर कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। हदोई स्थित संडीला के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार सिंह पर जनपद में नियमविरूद्ध अनधिकृत रूप से प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों पर कोई कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। जांच में आरोप सही पाए गए हैं। डॉ. सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही व जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जनपद में कई वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की तैनाती के बावजूद कनिष्ठ चिकित्साधिकारी को वरिष्ठ पद का कार्य कराये जाने के लिए सीएमओ से जवाब-तलब किया गया है।लंबे समय से गैरहाजिर पांच डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। इन डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष को दिए हैं। इन्हें सेवा से बर्खास्त किए जाएगा। गोरखपुर जिला चिकित्सालय की डॉ. अलकनन्दा, कुशीनगर सीएमओ के अधीन डॉ. रामजी भरद्वाज, बलरामपुर सीएमओ के अधीन डॉ. सौरभ सिंह, अमेठी स्थिति जगदीशपुर सीएचसी के डॉ. विकलेश कुमार शर्मा व औरैया दिबियापुर सीएचसी की डॉ. मोनिका वर्मा पर बर्खास्तगी की गाज गिरेगी। प्रयागराज मेजा सीएचसी के अधीक्षक डॉ. शमीम अख्तर पर कोरांव सीएचसी अधीक्षक रहते हुए प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। साथ ही अधीनस्थों पर नियंत्रण न रख पाने एवं अन्य कई गम्भीर शिकायतों के कारण विभागीय कार्यवाही किये जाने एवं तबादला किये जाने के आदेश दिये गये हैं। सुल्तानपुर के लम्भुआ सीएचसी में महिला के इलाज में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार सिंह (वर्तमान तैनाती-सीएचसी कादीपुर), डॉ. धर्मराज, चिकित्साधिकारी एवं सीएचसी-लम्भुआ में तैनात फार्मासिस्ट अवधनारायण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

युवक ने सट्टे के कर्ज से परेशान होकर गुरुवार रात जान दे दी

कानपुर में एक युवक ने सट्टे के कर्ज से परेशान होकर गुरुवार रात जान दे दी। युवक ने पहले होटल में कमरा बुक कराया और फिर उसी कमरे में पंखे से लटक कर सुसाइड किया। देर रात तक कमरे से कोई आवाज न आने पर होटल कर्मचारियों को शक हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। मृतक की पहचान रावतपुर थाना के मस्वानपुर सराय निवासी प्रशांत दीक्षित (27) के रूप में हुई। प्रशांत प्राइवेट नौकरी करते थे। परिवार में मां अर्चना दीक्षित, पत्नी अंशिका दीक्षित और डेढ़ साल की बेटी भाव्या हैं। मृतक के बहनोई दीप अग्निहोत्री ने बताया कि प्रशांत टाटा कंपनी में नौकरी करता था। गुरुवार सुबह रोज की तरह ऑफिस जाने की बात कहकर घर से निकला था। दिनभर परिजनों ने कई बार उन्हें फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। दो दिन पहले पड़ोसी युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी। कल्याणपुर के होटल रास प्लाजा में प्रशांत का दोस्त काम करता है, यहीं गुरुवार सुबह 10 बजे प्रशांत कमरा लेकर रुका। गुरुवार रात करीब 8 बजे होटल मालिक आदित्य को कर्मचारी ने बताया कि उनका दोस्त प्रशांत सुबह से न तो बाहर निकला और न ही कमरे से कोई आवाज आ रही है। कर्मचारियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सूचना पर होटल मालिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। प्रशांत के मोबाइल पर कॉल की गई तो फोन बंद मिला। इसके बाद होटल मालिक ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरा नंबर-302 का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। कमरे में प्रशांत का शव पंखे से चादर के सहारे लटका मिला। इसके बाद होटल पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए।

कानूनी संकटों में घिरी आई-पैक उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए प्रस्तावित गठबंधन तोड़ दिया

खबरों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सलाहकार फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के साथ प्रस्तावित समझौते को रद्द करने का फैसला किया है। यह कदम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन और कथित बंगाल कोयला तस्करी मामले में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आई-पीएसी निदेशक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी सहित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सपा और आई-पैक के बीच समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका था, और कंपनी ने पार्टी नेतृत्व को अपना चुनावी खाका भी पेश कर दिया था। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आई-पैक को नियुक्त करने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने टीएमसी नेतृत्व के कहने पर ही आई-पैक की प्रस्तुति पर विचार किया था। सूत्रों ने आगे बताया कि कंपनी के सामने अब कई चुनौतियां हैं, इसलिए सपा द्वारा आगे की बातचीत करने की संभावना कम है। आई-पैक, जो 2019 से टीएमसी के चुनाव प्रचार का प्रबंधन कर रही है, ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रही सपा को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी। दूसरी ओर, सूत्रों का यह भी दावा है कि कई मोर्चों पर संकटों से जूझ रही आई-पीएसी फिलहाल नए कार्यभार लेने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता स्थित आई-पीएसी कार्यालय पर छापा मारा, जिसके चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एजेंसी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अब प्रतीक जैन के नेतृत्व वाली इस फर्म की स्थापना जन सूरज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने की थी, जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 2017 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सहित कई राजनीतिक नेताओं के चुनाव अभियानों को डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध हुए।

ओमप्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओमप्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम पार्टियों पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम पर बोलते हुए राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि बंगाल का रिजल्ट आया तो अखिलेश यादव बेहोश हो गए, वह 4 घंटे बेहोश रहे। अब इनको पता है कि इन्हें सत्ता में वापस आना नहीं है। ममता बनर्जी भी संविधान को नहीं मानती हैं। अखिलेश यादव भी नहीं मानते हैं, इसलिए कोलकाता जा रहे हैं। अखिलेश ने महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के नतीजे देख लिए हैं। आरजेडी से लेकर टीएमसी पर निशाना साधते हुए ओपी राजभर ने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सभी दगे हुए कारतूस हैं। वहीं, I-PAC पर राजभर बोले कि कोयला घोटाले का पैसा था। अब पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं रहीं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव, बंगाल जा रहे हैं तो थोड़ी सी झालमुड़ी खाकर आइएगा। दीदी बहुत अच्छा बनाती हैं। वहीं, अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इनका पीडीए तो सिर्फ डिंपल और अखिलेश हैं। ओपी राजभर ने ये भी कहा कि टीपू भैया, कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं लेकिन 20 साल मौका नहीं मिलेगा।